प्रतिदिन

नए महामहिम की सोच

चौदहवें *राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद रामनाथ कोविंद ने हिन्दी में दिए अपने भाषण में जो कुछ कहा, उससे देश और दुनिया के बारे में उनकी पूरी सोच स्पष्ट होती है. वह भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि एक नैतिक और आदर्श शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया को दिशा दे सके. गुलामी के दौरान आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे मनीषियों की भविष्य के भारत के बारे में यही कल्पना थी. राष्ट्रपति कोविंद ने इस संदर्भ में महात्मा गांधी और जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का उचित ही उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस समय महात्मा बुद्ध के इस देश को शांति और अहिंसा के लिए दुनिया का नेतृत्व करने की जरूरत है. तो भारत को विश्व के स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे नये राष्ट्रपति देखना चाहते हैं. किंतु यह होगा कैसे? इसका भी विचार उन्होंने दिया.*

राष्ट्रपतिजी ने आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 तक भारत को आर्थिक एवं सामाजिक दोनों रूपों में विकसित करने की बात की. इस संदर्भ में उनके द्वारा संविधान निर्माता डॉ. बी.आर.अम्बेडकर का उल्लेख किया जाना स्वाभाविक था, जो बगैर सामाजिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता को अधूरा मानते थे. कोई देश तभी सशक्त हो सकता है, जब वह सामाजिक असमानता की खाई से अपने को दूर करे. यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है. राष्ट्रपति ने कई बार राष्ट्र निर्माण की बात की. उन्होंने एक सामान्य खेतिहर मजदूर से लेकर प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों तक; हर वर्ग को राष्ट्र निर्माता करार दिया. वास्तव में अकेले कोई सरकार किसी राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती. जनता का हरेक वर्ग जब तक अपनी जिम्मेवारियों का पालन नहीं करता राष्ट्र को विकास के उच्चतम शिखर तक ले जाना संभव नहीं हो सकता. वैचारिक सहिष्णुता और विविधता में एकता पर उनका खास जोर था. हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, पर एक-दूसरे से असहमत होते हुए भी सम्मान करना और विविधता होते हुए भी एकता का अनुभव करना ही हमारे सच्चे भारतीय होने का परिचायक है. इस तरह, नये महामहिम ने अपने पहले भाषण से देश के अंदर राष्ट्र निर्माण की एक समग्र, संतुलित और व्यावहारिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया है. यह भाषण ही विश्वास दिलाता है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की हर कसौटियों पर खरे उतरेंगे.

राष्ट्रपति रहे हमारे प्रणबदा...

सिरहाने जिनके संविधान रहा

प्रणबदा की सेवानिवृत्ति के बाद एक सवाल आया है कि क्या वे वापस जाकर कांग्रेस की सेवा करेंगे? भारत में राष्ट्रपति पद से निवृत्ति के बाद राजनीति में वापस जाने की परंपरा नहीं है. उम्मीद है कि प्रणब मुखर्जी भविष्य में जो बोलेंगे या लिखेंगे, वह देश के नेता के रूप में होगा, पार्टी के नेता के रूप में नहीं.

प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को लेकर हाल में जो टिप्पणियां आई हैं, उनमें 'कांग्रेसमुखी' विश्लेषकों के लेखन में प्रणब मुखर्जी की मोदी के प्रति नरमी को लेकर खिन्नता व्यक्त होती है. उन्हें लगता है कि प्रणब मुखर्जी को मोदी की फजीहत करनी चाहिए थी. उनके भीतर के कांग्रेसी को जागना चाहिए था. पर ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने केवल संविधान की भावना को निर्देशक सिद्धांत माना.ऐसी सूचनाएं भी हैं कि उन्होंने हर बार सरकार से पूरी जानकारियां हासिल कीं. बार-बार अध्यादेश जारी करने की उन्होंने खुली आलोचना भी की. कांग्रेसी तौर-तरीकों की आलोचना में भी वे पीछे नहीं रहे.

प्रणब मुखर्जी बड़े विकट समय में राष्ट्रपति रहे. यूपीए सरकार के अंतिम दो साल राजनीतिक संकट से भरे थे. सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, अर्थव्यवस्था अचानक ढलान पर उतर गई थी, और सत्तारूढ़ दल भी नेतृत्वविहीन नजर आने लगा था. यूपी सरकार के जाने के बाद एक ताकतवर राजनेता प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली आया तो राजनीति में जबर्दस्त बदलाव की लहरें उठने लगीं. ऐसे में राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने जिस संयम और धैर्य के साथ काम किया, वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है.

प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं. उनके सामने पिछले दो साल में ऐसे अनेक मौके आए होंगे, जब उनके निर्णयों को लेकर राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा सकते थे. ऐसा हुआ नहीं. उनके पहले दो साल के कार्यकाल में इस बात की संभावना नहीं थी, पर अंतिम तीन साल में थी. पर वे अत्यंत संतुलित, सुलझे हुए राष्ट्रपति साबित हुए. संसदीय व्यवस्था के सुदीर्घ अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हर मौके पर वही किया, जिसकी एक राजपुरुष यानी स्टेट्समैन से अपेक्षा की जाती है. संविधान में लिखे अक्षरों और उनके पीछे की भावना का पूरा सम्मान और अपने विवेक का इस्तेमाल.

प्रणबदा की सेवानिवृत्ति के बाद एक सवाल आया है कि क्या वे वापस जाकर कांग्रेस की सेवा करेंगे? भारत में राष्ट्रपति पद से निवृत्ति के बाद राजनीति में वापस जाने की परंपरा नहीं है. उम्मीद है कि प्रणब मुखर्जी भविष्य में जो बोलेंगे या लिखेंगे, वह देश के नेता के रूप में होगा, पार्टी के नेता के रूप में नहीं.

मणिशंकर अय्यर ने अपने एक लेख में कहा है, घर वापसी पर आपका स्वागत है प्रणब दा. और यह भी कि उन्हें अब कांग्रेस के सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए. बेशक, कांग्रेस आज संकट में है. उसे रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है पर क्या प्रणब मुखर्जी की इच्छा उसे रास्ता दिखाने की है? सलाहकार ही बनना है तो पूरे देश के बनें. केवल कांग्रेस के ही क्यों?

राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का दर्जा क्या पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं हो गया है? सवाल दोनों से है. प्रणब दा की इच्छा क्या है और कांग्रेस क्या चाहेगी? क्या वह समझना चाहेगी कि उससे कहां गलती हो रही है? प्रणब दा के पास राजनीतिक ज्ञान, अनुभव और विवेक का वह भंडार है, जिसके आधार पर वे देश के प्रधानमंत्री बनते, पर ऐसा नहीं हुआ. वे राष्ट्रपति बने और उस पद की गरिमा का उन्होंने पूरी तरह पालन किया.

भारत में राष्ट्रपति को 'रबर स्टैम्प' माना जाता है. इस पद की अपनी गरिमा है और कुछ मौकों पर राष्ट्रपति के विवेक की परख भी होती है. मसलन, यदि मई, 2014 के लोक सभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता तो राष्ट्रपति के विवेक की परीक्षा भी होती. संयोग से ऐसा नहीं हुआ, पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस बात का अंदेशा तो हमेशा ही था कि कांग्रेसी राष्ट्रपति और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की कैसे बनेगी? हाल में राष्ट्रपति भवन में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी की जिस अंदाज में तारीफ की, वह असामान्य थी.

मोदी ने उस भाषण में प्रणब मुखर्जी को पिता तुल्य बताया. उन्होंने कहा, 'जब मैं दिल्ली आया तो मुझे गाइड करने के लिए मेरे पास प्रणब दा मौजूद थे. मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ कर दिल्ली की जिंदगी में खुद को स्थापित करने का मौका मिला.'

प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को लेकर हाल में जो टिप्पणियां आई हैं, उनमें 'कांग्रेसमुखी' विश्लेषकों के लेखन में प्रणब मुखर्जी की मोदी के प्रति नरमी को लेकर खिन्नता व्यक्त होती है. उन्हें लगता है कि प्रणब मुखर्जी को मोदी की फजीहत करनी चाहिए थी. उनके भीतर के कांग्रेसी को जागना चाहिए था. पर ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने केवल संविधान की भावना को निर्देशक सिद्धांत माना.

प्रधानमंत्री के वक्तव्य से यह भी पता लगता है कि प्रणब मुखर्जी ने अपने अनुभव के आधार पर उन्हें रास्ता भी दिखाया. यह उनका अनुभव ही था कि जब प्रणब मुखर्जी इजराईल की यात्रा पर गए तो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि इस यात्रा में फिलिस्तीन को भी जोड़ना चाहिए. यह राजनीतिक सलाह नहीं थी, राष्ट्रपति के रूप में देशहित में थी.

ऐसे तमाम प्रसंग आए होंगे. आलोचक मानते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने जोखिम नहीं उठाया और सरकार से सहयोग किया. उत्तराखंड में राज्यपाल की संस्तुति की परीक्षा किए बगैर राष्ट्रपति शासन लागू करना ठीक नहीं था. अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल किए बगैर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया. भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश बार-बार जारी हुआ. राज्यपालों को हटाने और नियुक्त करने की प्रक्रिया चली. प्रणब मुखर्जी ने वही किया जो सरकार ने कहा. ऐसी सूचनाएं भी हैं कि उन्होंने हर बार सरकार से पूरी जानकारियां हासिल कीं. बार-बार अध्यादेश जारी करने की उन्होंने खुली आलोचना भी की. कांग्रेसी तौर-तरीकों की आलोचना में भी वे पीछे नहीं रहे. मसलन, 'पुरस्कार वापसी' के दौर में उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय पुरस्कारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें संरक्षण देना चाहिए.' संसद में शोर मचाने का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया. उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र की हमारी संस्थाएं दबाव में हैं. संसद परिर्चचा के बजाय टकराव के अखाड़े में बदल चुकी है.'

प्रणब मुखर्जी चाहते तो कांग्रेस के प्रति अपने झुकाव को व्यक्त करते. उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसमें दो राय नहीं कि वैचारिक रूप से वे कांग्रेसी मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास का संकलन किया है. बेशक, वे मानते हैं कि भारतीय समाज को एक साथ रखने वाली छतरी कांग्रेस के पास ही है. पर क्या पार्टी में अभी उनकी कोई भूमिका है? क्या वे खुद इस दिशा में उत्सुक हैं? देखें और इंतजार कर

सुबोध बनर्जी.

इंटरनेशनल मीडिया

शांति भंग की कोशिशें

जाफना में हुए घातक हमले में जज एम.इलांचेलियन जिस तरह बाल-बाल बचे, वह पूरे देश के लिए राहत की खबर है. एक अज्ञात में हैं. सरकार का असली काम ऐसे तत्वों पर नजर रखते हुए देश को अशांति से बचाना होना चाहिए. खासतौर से ऐसे वक्त में, जब

Daily News

व्यक्ति ने जिस तरह उनके सुरक्षाकर्मी की रिवाल्वर छीनकर गोलियां चलाईं, वह कई सवाल खड़े कर गया है. देश के कई हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई कर चुके इलांचेलियन अपने साहसिक फैसलों के लिए चर्चित हैं. इन दिनों भी वह मई, 2015 के चर्चित जाफना बलात्कार व हत्याकांड की सुनवाई कर रहे हैं, जिस पर काफी हंगामा हुआ था. यह हमला उस पुलिस अफसर ललित जयसिंघे की गिरफ्तारी के अगले दिन हुआ, जो घटना के वक्त जाफना का एसएसपी था और जिस पर मामले के मुख्य आरोपी को देश से भागने में सहयोग का आरोप है. इस मामले में एक और पहलू पर ध्यान देना होगा. नहीं भूलना चाहिए कि 1983 के सांप्रदायिक दंगों की 34वीं वर्षगांठ के रूप में 23 जुलाई याद की गई. श्रीलंका भले ही उस स्याह दौर को भूल जाना चाहता हो, लेकिन तमाम लोग हैं, जो मौका मिलते ही आज भी सौहार्द और स्थायी शांति का माहौल बनाने की दिशा में ठोस प्रयास ही नहीं हो रहे, सकारात्मक नतीजे भी मिले हों.

यह भी तय है कि चंद नस्लवादी नेताओं को देश की शांति और सुलह प्रक्रिया भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसलिए इस घटना को एक गंभीर अलार्म के रूप में लेने की जरूरत है. जरूरी है कि न सिर्फ इस कांड की सुनवाई कर रहे जजों और अदालत, बल्कि मामले से जुड़े हर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो. छोटी से छोटी वारदात को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें पिछले दिनों सामने आती रही हैं. यह सही है कि देश में अदालतों के निडर और निष्पक्ष होकर काम करने का माहौल बना है, लेकिन सिर्फ न्याय व्यवस्था को निडर और निष्पक्ष बना देने से मकसद पूरा नहीं होगा. देश की पुलिस के लिए भी ऐसा ही माहौल बनाना होगा, तब जाकर निष्पक्ष और निडर न्याय की संकल्पना साकार हो सकेगी.

द डेली न्यूज, श्रीलंका.

प्रतिदिन

कल की चिंता

एक शहर में धर्मदत्त नामक सेठ रहता था. अपार संपत्ति का स्वामी होने के बावजूद वह हमेशा उदास रहा करता था. उसे अपनी भावी पीढ़ी की चिंता सताती रहती थी. एक बार

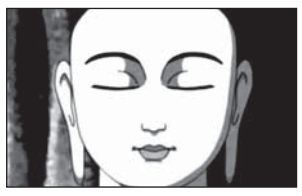

भगवान महावीर उस शहर में आए. गंगा के तट पर उनका प्रवचन हो रहा था. धर्मदत्त भी वहां पहुंचा. वह पहली कतार में बैठे कर प्रवचन सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था. प्रवचन के बाद भगवान महावीर ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सेठ ने कहा- प्रभु, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है. मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरी सात पीढियां आराम से खा-पी सकें. लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी आठवीं पीढ़ी का गुजर-बसर कैसे होगा? भगवान महावीर ने कहा- तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देता हूं. तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम्हारी आठवीं पीढ़ी सुख से रहेगी. इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा. यहां एक आश्रम के पीछे झोपड़ी में एक मजदूर का परिवार रहता है. तुम उससे कहो कि वह अपनी आवश्यकता का आटा अपने पास रख कर बाकी तुम्हें दे दे. सेठ वहां गया और उसने वैसा ही कहा. मजदूर की पत्नी घर के अंदर से एक हंडिया ले आई और उसे देते हुए बोली- ले जाओ भाई. मेरे पास इतना ही आटा है.सेठ ने कहा, नहीं, नहीं, तुम अपनी जरुरत का आटा रख लो, जो बचे उसे दो. मजदूर की पत्नी बोली- अगर मैंने अपनी जरुरत का आटा रख लिया तो तुम्हें क्या दूंगा. मुझे जिसने आज दिया,कल भी देगा. सेठ खाली हाथ लौट आया और उसने भगवान महावीर को सारी बात बताई. भगवान महावीर बोले- सेठ एक वह मजदूर स्त्री है, जिसे कल की भी चिंता नहीं है और एक तुम हो कि अपनी आठवीं पीढ़ी की चिंता में अपने को गला रहे हो. क्या तुम्हारी आगामी पीढ़ी अपाहिज, काहिल और निकम्मी होगी कि जिसके लिए तुम चिंतित हो. उस दिन से सेठ ने चिंता करनी छोड़ दी.

नेटीजन

आम आदमी का वैज्ञानिक

एक प्रोफेसर इस दुनिया से नहीं गया, यशपाल जी के साथ बच्चों का अभिभावक चला गया है.

वे वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिकों से अलग थे. सोच अलग ही रही. वैज्ञानिक सोच और उसे बच्चों में उतारना उनकी अलग ही खूबी रही. लंदन में एक अंग्रेज बच्चे को एक हिन्दुस्तानी बच्चे ने जलेबी दी खाने को. अंग्रेज के बच्चे ने जलेबी खाई, फिर गौर से जलेबी को देखा और कुतूहल सामने था इस टेढ़ी-मेढ़ी मिठाई में चीनी कैसे डाली गई? सवाल गया टीचर के पास. हिन्दुस्तान का टीचर होता, तो अनुशासन का डंडा दिखाकर चुप करा देता, लेकिन मामला लंदन का रहा. सो साहब, यह सवाल दूतावास से होते हुए देश में आ गिरा. और इसका जवाब जिस वैज्ञानिक ने दिया, वह थे प्रोफेसर यशपाल. इस तरह के अनगिनत सवालों के जवाब लिखकर प्रोफेसर यशपाल ने बच्चों को बहुत कुछ दिया है. बच्चे बहुत प्रिय रहे प्रोफेसर यशपाल को. विदेश में एक बार (देश का नाम याद नही है) दो लोग, दोनों ही वैज्ञानिक बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे. पूर्व राष्ट्रपति कलाम और प्रोफेसर यशपाल. कलाम साहब बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे थे, बीच-बीच मे बोलते, 'एम आई राइट प्रोफेसर साब?' अंत में, प्रोफेसर साहब ने अपील कर डाली, बस्ता मत ढोओ या वजन कम कर दो. हमारे बीच से एक प्रोफेसर नहीं गया है, बच्चों का सच्चा अभिभावक चला गया है. **चंचल की फेसबुक वॉल**

मणिपुर

खतरे में नवाज की कुर्सी

तीन बार के निर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दिनों अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ पनामा लीक्स से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और समूचा विपक्ष एकजुट होकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है.

पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें, तो पहले भी दो बार नवाज शरीफ और उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा चुका है. लेकिन उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और दोनों बार वह फिर प्रधानमंत्री बनकर लौटे. इस बार गलती नवाज शरीफ की भी है, जो मौका दिये जाने के बाद भी अपने और अपने परिजनों की आय के स्रोत बताने में विफल रहे.

हाल ही में प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगने वाली विपक्षी पार्टियों की आलोचना की है. इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ समेत अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इस गंदी राजनीति में शामिल हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि उनका काम मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है. उन्होंने कहा, मुल्क यह नाटक 2014 से ही देख रहा है, जब सरकार को गिराने के लिए एक धरना आयोजित किया गया था, जिन्हें मुल्क ने कई बार खारिज किया, वही मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मजम्मत करते हुए शरीफ ने कहा कि 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो ने उनके परिवार की एक फैक्टरी का जबरन राष्ट्रीयकरण कर दिया था. मुझे कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया. यह पहली बार है, जब मैंने प्रधानमंत्री निवास में चार साल पूरे किए हैं. अब देखना है कि आगे क्या होता है!

अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुस्लिम लीग के वरिष्ठ राजनेताओं पर टिकी हैं कि वे कैसे प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं. खबरें हैं कि उनके कुछ मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, वह इस्तीफा दे दें. राजनीतिक विश्लेषक जाहिद हुसैन कहते हैं कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि पदासीन प्रधानमंत्री को कानून के दायरे में लाए जाने से चीजें बदल जाएंगी. लेकिन इस अप्रत्याशित कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का अवसर मिल सकता है. निश्चित रूप से इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जजों ने अपनी भूमिका स्वतंत्रतापूर्वक निभाई है. अगर न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं ठीक से अपना काम न करें, तो लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता.

एकमात्र इमरान खान ही ऐसे विपक्षी नेता हैं, जिनसे नवाज शरीफ को पंजाब प्रांत में मुश्किलें हो सकती हैं. यदि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को दोषी पाती है और उन्हें राजनीति के अयोग्य बताती है, तो पंजाब की सत्ता पर कब्जा पाने का इमरान खान को अच्छा मौका मिल सकता है. पंजाब पाकिस्तान का ऐसा प्रांत है, जो प्रधानमंत्री बना और हटा सकता है. ऐसी खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ संसद में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं, जो उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री का पदभार संभाल सके, क्योंकि उनकी सरकार का कार्यकाल मई, 2018 में खत्म होगा. कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शहबाज ने कहा है कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी परियोजनाएं पूरी करनी हैं. आने वाले महीने उथल-पुथल भरे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे, मुल्क में लोकतंत्र पटरी ने नहीं उतरेगा और मई, 2018 तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहेगी.

मो. अशरफ.

सुविचार

तेरे गिरने में, तेरी हार नहीं, तू इन्सान है,
अवतार नहीं...
गिर, उठ, चल, दौड, फिर भाग क्योंकि,
जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं...

आपकी बात

सोचो..समझो..करो

समझ से ही बाहर है कि आजकल ये हो क्या रहा है.देश की सीमा की अंदर लगातार घुसपैठ जारी है तो देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है. शहर-गांवों में अपनी बात या अपनी मांग के लिये हर तरह की नाटक-नौटंकी जारी है.कहावत है कि, 'नाक दबाओ तो मुंह खुलता है', पर इतनी भी नाक मत दबाओ कि देश की जान ही निकल जाए.

सत्य-अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने 'सत्याग्रह' के बल पर ही देश को आजादी दिलाई थी, और आज सत्याग्रह के नाम पर जो आंदोलन चल रहे हैं उन पर भी एक नजर डाल लीजिये.सरकारी ऑफिस की कुर्सी-टेबले फेंकी जा रही हैं,जलाई जा रही हैं.तमाचे की गूंजें परिसर में सुनाई दे रही हैं. कभी गहराई से झांकिये,तो जनता के नाम किये जा रहे अधिकांश आंदोलनों के पीछे किन्हीं चुनिंदा लोगों के स्वार्थ ही छुपे होते हैं.आज पटरी से उतरी जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था नजर आती है, वह हम और हमारे बाप-दादों की करनी का ही नतीजा है.अगर कोई सोचता है कि 'बाहुबली' बनकर व्यवस्था सुधारी जा सकती है,तो सुधार लीजिये, बिना यह भूले कि आपसे भी बड़ा बाहुबली आपके पास ही कहीं हो सकता है. कितना ही आंदोलन कर लें, खुली सड़क पर तो सुलझने से रही, आखिर में तो 'बात' से ही समस्या सुलझेगी. तो क्यों न ओहदेदार और जनता में समन्वय साधा जाए. 'सोचो-समझो-करो' पर चलते हुए अपने कृत्यों को अंजाम दें, कुछ देर लगेगी, पर नतीजा जरुर दिखाई देगा.

मोहनसिंह रघुवंशी,नांदगांवपेठ.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.